



- शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति की सकारात्मक पहल। सीमा, शांति और व्यापार सहयोग पर दोनों देशों की बनी सहमति।
- आकाशवाणी से मन की बात की एक सौ पच्चीसवीं कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जीवन से जुड़ी हर चीज़ स्वदेशी होनी चाहिए।
- सांसद विष्णु पद रे की पहल, द्वीपसमूह के ढाई सौ स्कूलों को मिलेगी नई तकनीकी ताकत।
- महिला एथिलीटों के लिए आयोजित होने वाली अस्मिता रग्बी सेवेन्स लीग बीस सितंबर से शुरू होगी।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिगपिंग ने कहा है कि दोनों देश परस्पर विकास के भागीदार हैं, न कि एक-दूसरे के विरोधी और उनके मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए। श्री मोदी और श्री जिगपिंग ने चीन के तियानचिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में मुलाकात के दौरान ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति बनाए रखना आपसी संबंधों के निरन्तर विकास के लिए जरूरी है। दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों की वापसी पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने सीमा मुद्दे के निष्पक्ष, तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य समाधान पर सहमति व्यक्त की ताकि समग्र द्विपक्षीय संबंध और दोनों देशों के दीर्घकालिक हित बने रहें। भारत और चीन ने दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंधों को मजबूत करने और सीधी उड़ान तथा वीजा सुविधा शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा और पर्यटक वीजा बहाली पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन के संबंधों को तीसरे देश की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि आतंकवाद और निष्पक्ष व्यापार जैसे मुद्दों और चुनौतियों पर वैश्विक मंचों पर साझा रुख अपनाना जरूरी है।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने यानी वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की एक सौ पच्चीसवीं कड़ी में उन्होंने कहा कि त्योहारी मौसम के दौरान देशवासियों को स्वदेशी को ध्यान में रखना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि उपहार, कपड़े और साज-सज्जा की वही चीजें लें, जो मेड इन इंडिया यानी भारत में बने हों अथवा भारत की सामग्री से तैयार हुए हों। जीवन से जुड़ी हर चीज स्वदेशी होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने डिजिटल ऐप प्रतिभा सेतु की चर्चा की जिसमें उन परीक्षार्थियों का डेटा सुरक्षित रखा जाता है जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग-यूपीएससी की परीक्षाओं के हर चरण को पार तो किया, लेकिन अंतिम मेधा-सूची में जगह नहीं पा सके। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के ज़रिए निजी कंपनियां इन संभावनाशील विद्यार्थियों से जुड़ी जानकारी लेकर उन्हें रोज़गार दे सकती हैं। श्री मोदी ने कहा कि इसके परिणाम आने शुरू भी हो गए हैं और ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थियों को इस पोर्टल के माध्यम से तुरंत रोज़गार मिला जो बहुत मामूली अंतर से चूक गए थे। अब ये परीक्षार्थी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं।



प्रधानमंत्री ने इटली के शहर कैम्प रोतोंदो में महर्षि वाल्मीकि और कनाडा के मिस्सीससोगा में भगवान श्रीराम की प्रतिमाओं के अनावरण का भी जिक्र किया।

इसके साथ ही श्री मोदी ने इंजीनियर समुदाय की प्रशंसा करते हुए कहा कि शिल्पकार हमेशा से भारत की समृद्धि का आधार रहे हैं।



अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और तकनीकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए सांसद विष्णु पद रे ने केंद्र सरकार को तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजे हैं। ये योजनाएं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आर्थिक सहयोग से लागू की जाएंगी। सांसद रे ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर पचास स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब्स स्थापित करने की सिफारिश की है, जिससे छात्रों में नवाचार और तकनीकी कौशल को बढ़ावा मिलेगा। यह कार्य UNISED संस्था द्वारा किया जाएगा। दूसरे प्रस्ताव में, उन्होंने सौ स्कूलों में आई.सी.टी लैब्स स्थापित करने का अनुरोध किया है, जिसे

एनी केयर फाउंडेशन द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। तीसरे प्रस्ताव में, सांसद ने कोयला एवं खनिज राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे को पत्र लिखकर सौ स्कूलों में सोलर-पावर्ड स्मार्ट क्लासेस और जॉयफुल लर्निंग लैब्स शुरू करने की मांग की है। सांसद ने कहा कि द्वीपों की भौगोलिक दूरी और सीमित संसाधनों के कारण बच्चों को समान शिक्षा नहीं मिल पाती। ये योजनाएं डिजिटल गैप को कम करेंगी और छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएंगी।



इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसने पूरे भारत में डिजी लॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर ई-गवर्नेंस सेवाओं के एकीकरण को सक्षम बनाया है। इस उपलब्धि के साथ, अब देश के सभी छत्तीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक किसी भी समय, कहीं से भी, लगभग दो हजार डिजिटल सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इन सेवाओं में प्रमाणपत्र, कल्याणकारी योजनाएँ, बिल भुगतान और अन्य नागरिक सुविधाएँ शामिल हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों को सुविधाजनक, पारदर्शी और पेपरलेस सेवाएँ उपलब्ध कराना है। डिजी लॉकर अब भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढाँचे का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। पूरे देश में कुल मिलाकर अभी तक एक हजार नौ सौ अड़तीस सेवाएँ में उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन नई तकनीकें जैसे ए.आई अपनाकर सेवाओं का विस्तार करेगा और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। यह कदम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल और समावेशी भारत के विज़न को साकार करने की दिशा में है।



भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण की एक पहल के तहत श्री विजयपुरम में अस्मिता रग्बी सेवेन्स लीग बीस सितंबर, को आयोजित की जाएगी। अस्मिता लीग, जिसे पहले खेलो इंडिया महिला लीग के नाम से भी जाना जाता था। इसका उद्देश्य देश भर में विभिन्न आयु वर्ग की महिला एथलीटों को प्रतिस्पर्धात्मक अवसर प्रदान करना है। भाग लेने वाली इच्छुक टीमों पन्द्रह सितम्बर तक नेताजी स्टेडियम स्थित राज्य ओलंपिक कार्यालय, में रजिस्ट्रेशन करा सकती है। इसके अलावा, यदि किसी टीम को प्रशिक्षण और टीम निर्माण के लिए कोच की आवश्यकता होती है, तो एसोसिएशन लीग में बेहतर तैयारी और प्रदर्शन के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता प्रदान करेगा।



द्वीपसमूह में आज सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान विभिन्न स्थानों पर हुई वर्षा इस प्रकार रही। लॉन्ग आइलैंड्स में पचपन मिमी, मायाबंदर में अड़तीस, हट बे में आठ, ननकौड़ी में दो दशमलव दो कार निकोबार दो, वायुसेना केन्द्र कार निकोबार में एक दशमलव चार मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। अगले चौबीस घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है। इस कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने सलाह दी गई है।

